



किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

❖ संदर्भ

➤ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने चारा केंद्रित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रचार का प्रस्ताव दिया है।

❖ मुख्य बिंदु

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- इसे 2022-23 के दौरान 100 एफपीओ निर्मित करने का कार्य सौंपा गया है।

❖ पृष्ठभूमि

- देश में चारे की कमी की स्थिति है।
- थोक मूल्य सूचकांक आधारित चारा मुद्रास्फीति अगस्त 2022 में नौ वर्ष के उच्च स्तर 25.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
- ग्रामीण परिवार जिनकी आजीविका पशुधन पर निर्भर है, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

❖ एफपीओ के विषय में

- एफपीओ एक संगठन है, जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA के अंतर्गत या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसमें निर्माता शेयरधारकों के रूप में हैं।

- वे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से निर्मित किये गए हैं।
- एफपीओ का गठन और प्रचार उत्पाद क्लस्टर क्षेत्र पर आधारित है जिसे एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां समान प्रकृति के कृषि और सम्बंधित उत्पाद पैदा किये जाते हैं।
- 2020 में प्रारम्भ की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना "10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" के अंतर्गत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एसएफएसी, नाबार्ड, नेफेड, एनसीडीसी, एनईआरएएमएसी जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एफपीओ के गठन को बढ़ावा देता है। आदि।
- कार्यान्वयन एजेंसियां प्रत्येक एफपीओ (FPO) को 5 वर्षों की अवधि के लिए व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (CBBOs) को शामिल करती हैं।

रुपये में व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय निपटान

❖ संदर्भ

➤ भारत रूस के साथ की जा रही व्यवस्था की तर्ज पर भारतीय रुपये में व्यापार प्रारम्भ करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है।



❖ मुख्य बिंदु

- भारत श्रीलंका, मालदीव और कई दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है।
- इन भौगोलिक क्षेत्रों के देशों ने विशेष रुपया वोस्त्रो या एसआरवी खाते खोलने में रुचि दिखाई है।
- वोस्त्रो खाता एक बैंक के पास एक खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसे जमा करने की अनुमति देता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार पर दिशानिर्देशों की घोषणा की थी।
- विशेष रुपया वोस्त्रो खाता खोलने वाला पहला देश रूस है।

❖ इस व्यवस्था के विषय में

- भारत में बैंक (अधिकृत डीलर) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात, व्यापार के लिए भागीदार देश के संपर्की बैंक/बैंकों के वोस्ट्रो खाते खोलें जा

❖ विगत व्यवस्था के विषय में

- भारत और सोवियत संघ के बीच इसी तरह की व्यवस्था 1953 से 1992 तक की गई थी।
- इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी स्वीकृति को टालना नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना और निर्यात को बढ़ावा देना था।
- प्रारंभ में, विनिमय दर का मूल्यांकन स्वर्ण के मानको के आधार पर किया गया था।
- बाद में इस तरह की प्रणाली का समर्थन करने के लिए वैश्विक स्वर्ण भंडार अपर्याप्त होने के साथ, 1978 के एक प्रोटोकॉल ने इसे 10 रुपये पर सेट किया और इसे संशोधित कर 31.78 रुपये कर दिया गया।
- रूस से आयातों के निर्यात से कहीं अधिक होने के कारण व्यापार संतुलन विषम था। सोवियत संघ के खातों में रुपया शेष बढ़ता रहा।
- इस व्यवस्था को अंततः 1992 में समाप्त कर दिया गया, और रुपये की शेष राशि

Face to Face Centres





10 November 2022

सकते हैं।
• भारतीय आयातक इन खातों में अपने आयात का भुगतान रुपये में कर सकते हैं।
• इन आय (भारतीय आयातों से) का उपयोग भारतीय निर्यातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

❖ इस व्यवस्था की चुनौतियाँ

• किसी भी देश के साथ इस व्यवस्था की सफलता की कुंजी विनिमय दर से निर्धारित की जाती है।
• भारत और एक देश, जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा है, के बीच कोई भी रुपया व्यापार व्यवस्था लंबे समय तक संभव नहीं हो सकती है।
• दूसरी चिंता यह है कि अगर बैंक रूस जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों से हैं तो इन खातों में संचित रुपये की राशि की दंड को आकर्षित किए बिना कैसे वापस किया जा सकता है।

को समाप्त करने में काफी समय लगा।

❖ इस बार की व्यवस्था में रूस के साथ क्या विविधताएं हैं?

• आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, दो व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर 'बाजार निर्धारित हो सकती है'।
• हालांकि भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा है लेकिन रूस एक अपवाद है क्योंकि देश प्रतिबंधों के अधीन है और यह रक्षा अनुबंधों के अंतर्गत अपने ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के लिए यहां निवेश करने के लिए भारतीय रुपये का उपयोग कर सकता है।
• चीन, स्विटजरलैंड, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया के साथ भारत का व्यापार घाटा अधिक रहा है।
• भारत का व्यापार अधिरोषण अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ रहा है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)

❖ संदर्भ

➤ हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधि आयोग से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत सहमति की आयु पर पुनर्विचार करने को कहा है।

❖ मुख्य बिंदु

• उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन:

- सहमति के कारक को 16 वर्ष की आयु लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की लड़की द्वारा माना जाना है।
- यह होना चाहिए अगर यह वास्तव में भारतीय दंड संहिता और/या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है।

पॉक्सो एक्ट के विषय में :

- बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है।
- यह इस प्रकार के अपराधों और संबंधित मामलों तथा घटनाओं के परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

❖ अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- यह एक लिंग-तटस्थ कानून है: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 'किसी भी व्यक्ति' के रूप में परिभाषित करके, पॉक्सो अधिनियम बाल यौन शोषण पीड़ित के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के लिए एक लिंग-तटस्थ स्वर सेट करता है।
- कदाचार की सूचना नहीं देना एक अपराध है: यह उन लोगों को दंडित करता है जो अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं या तो कारावास या

• यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर-प्रवेश करने वाला हमला, साथ ही साथ यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य शामिल हैं, जो यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले लोगों द्वारा दंडनीय भी हैं।
• यह विशेष अदालतों का प्रावधान करता है जो बच्चे की पहचान बताए बिना कैमरे पर और बच्चों के अनुकूल तरीके से सुनवाई करती हैं।
• यह जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल अभिभावक की भूमिका में भी रखता है।

• **पॉक्सो अधिनियम की शर्तें:** पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत भारत में सेक्स के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष है।

• 18 साल से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई सहमति को वैध नहीं माना जाता है और उसके साथ यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है।

❖ बाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर)

- यह पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- यह एक सांविधिक निकाय है।
- संसद के एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित।
- आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है।

Face to Face Centres





10 November 2022

जुर्माना या दोनों।

- दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं: पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि दुर्व्यवहार करने वाले के कई वर्षों के पश्चात भी।
- पीड़ित की पहचान की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।

- **संरचना:** एक अध्यक्ष और छह सदस्य जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए।
- इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए की जाती है।
- आयोग में सेवा करने की अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है।

खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन

❖ संदर्भ

➤ खान मंत्रालय ने कहा कि खनिजों के पूर्वेक्षण के संचालन के लिए 13 निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता दी गई है।



❖ मुख्य बिंदु

- अगस्त 2021 में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया ताकि केंद्र सरकार को निजी संस्थाओं सहित संस्थाओं को पूर्वेक्षण कार्य करने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार दिया जा सके।
- खान मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई-एनएबीईटी) के शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विकसित निजी जांच एजेंसियों के प्रत्यायन के लिए योजना को अपनाया है।
- क्यूसीआई-एनएबीईटी (QCI-NABET) खनिजों के पूर्वेक्षण कार्य करने के लिए निजी अन्वेषण एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा।

❖ एनएबीईटी (NABET) के विषय में

- यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संघटक बोर्ड है।
- इसने शैक्षिक संगठनों, व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठनों, प्रत्यायन प्रमाणन और कौशल प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए एक तंत्र स्थापित किया है।

❖ क्यूसीआई के विषय में

- यह यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशनों की सिफारिशों पर मान्यता के लिए एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में 1996 में एक कैबिनेट निर्णय के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- इसे भारत सरकार और भारतीय उद्योग के सहयोग से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में पीपीपी मॉडल के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों द्वारा किया जाता है, (i) एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), (ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और (iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की।
- यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत है।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (अब डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को क्यूसीआई से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

संक्षिप्त सुर्खियाँ

स्वामित्व योजना



❖ संदर्भ

- हाल ही में, स्वामित्व (SVAMITVA) योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की गई थी।
- यह मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है जिसे राज्य समग्र रूप से इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सकते हैं।

❖ मुख्य बिंदु

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित
- इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-

Face to Face Centres





2021) के सफल समापन के पश्चात लॉन्च किया गया था।

• **लक्ष्य :**

- ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करना ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें।
- यह ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि पार्सल की मैपिंग के लिए एक योजना है।

• **लाभ :**

- इस योजना के परिणाम में राजस्व/संपत्ति रजिस्ट्रारों में 'रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स' को अपडेट करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल होगा।
- यह ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त, इससे संपत्ति कर का स्पष्ट निर्धारण भी हो सकेगा, जो ग्राम पंचायतों को उपार्जित करेगा जिससे बेहतर नागरिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

केकड़े की नई प्रजाति



❖ **संदर्भ**

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने कुड्डालोर जिले (तमिलनाडु) में वेल्लर नदी के मुहाने के पास परंगीपेट्टई के मैंग्रोव में एस्ट्ररीन केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है।

❖ **मुख्य बिंदु**

- अन्नामलाई विश्वविद्यालय की शिक्षा और अनुसंधान में 100 वर्षों की सेवा के सम्मान में इस प्रजाति का नाम स्यूडोहेलिस अन्नामलाई रखा गया है।
- यह इस जीनस, स्यूडोहेलिस का अब तक का पहला रिकॉर्ड है।
- अब तक, इस जीनस के भीतर केवल दो प्रजातियों - स्यूडोहेलिस सबक्वाड्राटा और स्यूडोहेलिस लैट्रेली - की पुष्टि की गई है।
- **विशेषताएँ:** स्यूडोहेलिस अन्नामलाई गहरे बैंगनी से गहरे भूरे रंग के लिए, अनियमित हल्के भूरे, पीले भूरे, या हल्के भूरे रंग के चेलिपेड के साथ पीछे के आवरण पर सफेद पैच के साथ प्रतिष्ठित है। नई प्रजाति छोटी है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 20 मिमी तक है।
- **वितरण:** खोजी गई प्रजातियों को भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी हिंद महासागर के आसपास वितरित किया जाता है।

गरुड़ VII वायु अभ्यास



❖ **संदर्भ**

- हाल ही में, भारत और फ्रांस के वायु सेना प्रमुख जोधपुर में संचालित हो रहे वायु अभ्यास गरुड़ VII में शामिल हुए हैं।

❖ **मुख्य बिंदु**

- पूर्व गरुड़ VII हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस और हाल ही में शामिल किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में प्रतिभाग करने का प्रथम अवसर है।
- इस अभ्यास में फ्रांस की ओर से चार राफेल लड़ाकू विमान और एक ए-330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान शामिल हैं।
- एलसीए और एलसीएच के अलावा, भारतीय वायुसेना दल में सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और जगुआर लड़ाकू विमान, साथ ही एमआई-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं।
- द्विपक्षीय हवाई अभ्यास 2003 से संचालित हो रहा है।
- **महत्व:** वायु अभ्यास गरुड़ दोनों वायु सेनाओं को संचालन के दौरान एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।
- यह दोनों वायु सेनाओं के बीच बढ़ती अंतःक्रियाशीलता को उजागर करता है।

Face to Face Centres





नीलकुरिंजी



❖ संदर्भ

➤ नीलकुरिंजी अक्टूबर के पहले सप्ताह से केरल के इडुक्की में कालीपारा पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर खिले हुए थे।

❖ मुख्य बिंदु

- **वैज्ञानिक नाम** - स्ट्रोबिलैन्थेस कुंथियाना।
- यह महत्वपूर्ण घटना नीलकुरिंजी फूल का खिलना है, जो हर 12 वर्ष में एक बार दिखाई देता है।
- यह 40 या उससे अधिक किस्मों में खिलता है, जिनमें से अधिकांश का रंग नीला होता है।
- **वितरण**- यह एक झाड़ी है जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के शोला जंगलों में पाई जाती है।
- **आयाम**- उच्च स्थानों पर छोटी भिन्नता (लगभग 2 फीट) देख सकते हैं और निचले स्थानों पर लंबी विविधताएं (लगभग 5 से 10 फीट) देखी जा सकती हैं।
- तमिलनाडु में रहने वाले पलियान आदिवासी लोग इसे अपनी उम्र की गणना के लिए एक संदर्भ के रूप में उपयोग करते थे। इस पौधे में सितंबर-अक्टूबर में फूल आते हैं।
- कुरिंजिमाला अभयारण्य केरल के इडुक्की जिले में लगभग 32 किमी वर्ग में कोर निवास स्थान में कुरिंजी की रक्षा करता है।

गुजरात के अशांत क्षेत्र अधिनियम



❖ संदर्भ

➤ गुजरात सरकार ने अशांत क्षेत्र अधिनियम को मोरबी शहर के कुछ हिस्सों में बढ़ा दिया था, बावजूद इसके कि कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी।

❖ अधिनियम के विषय में

- अशांत क्षेत्रों में परिसर से बेदखली से अचल संपत्ति के हस्तांतरण और किरायेदारों के प्रावधानों के गुजरात निषेध अधिनियम, लोकप्रिय रूप से 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' के रूप में जाना जाता है।
- अधिनियम के अंतर्गत, एक जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी विशेष क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित कर सकता है। यह अधिसूचना सामान्यतौर पर क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के आधार पर की जाती है।
- इस अधिसूचना के पश्चात, अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल कलेक्टर द्वारा संपत्ति के खरीदार और विक्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करने के पश्चात ही हो सकता है।

2डीजी दवा



❖ संदर्भ

➤ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा बनाई गई दवा सार्स-कोव-2 (SARS-CoV-2) वायरस में एक प्रोटीन, एनएसपी6 (Nsp6) द्वारा लाए गए हृदय की क्षति का उपचार करने में सक्षम हो सकती है।

❖ मुख्य बिंदु

- फल मक्खियों और चूहों पर किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है।
- ओरल दवा 2डीजी (2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज) डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई गई थी।
- सार्स-कोव-2 वायरस को ऊर्जा पैदा करने के लिए ग्लूकोज या ग्लाइकोलाइसिस के विखंडन की आवश्यकता होती है।
- एनएसपी6 प्रोटीन ने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए फल मक्खी की हृदय कोशिकाओं को नियंत्रित किया है।
- हृदय कोशिकाएं सामान्यतौर पर फैटी एसिड का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करती हैं, लेकिन हृदय की विफलता के दौरान, जब ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने का प्रयास करती हैं, तो वे शुगर चयापचय में बपरिवर्तित हो जाती हैं।
- दवा वायरस के विकास को रोकती है और ग्लाइकोलाइसिस में बाधा डालती है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare

Face to Face Centres

